साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 10-16 अप्रैल, 2023, 2023, वर्ष-8, अंक-52

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

शिवराज देंगे राहत: कर्ज माफी के चक्कर में डिफाल्टर हो गए किसान, भारी भरकम ब्याज भी चढ़ गया

प्रदेश के 11 लाख किसानों की ब्याजमाफी करेगी मप्र सरकार!

साढ़े चार लाख किसानों को नहीं मिल रहा खाद व बीज

भोपाल। जागत गांव हमार

बैंकों और सहकारी समितियों से कर्ज लेने वाले किसानों को कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में दो लाख तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। साल 2018 में कमलनाथ की सरकार बनी तो 50 हजार तक के कर्ज माफ भी हुए। लेकिन 50 हजार से दो लाख तक का ऋण लेने वाले किसान कर्ज माफी के चक्कर में डिफाल्टर हो गए। इन किसानों पर कर्ज की राशि के अलावा भारी भरकम ब्याज भी चढ़ गया। डिफाल्टर हुए किसान खाद और बीज के लिए परेशान हो रहे हैं। अब कांग्रेस फिर कर्जमाफी करने की बात कह रही है वहीं भाजपा कमलनाथ की कर्जमाफी स्कीम के चक्कर में डिफाल्टर हुए किसानों का ब्याज माफ करने की बात कह रही है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने कर्जमाफी का झूठा वादा किया था। कमलनाथ ने कर्जा माफ नहीं किया और कर्जामाफी के चक्कर में कई किसानों ने पैसे नहीं भरे और डिफाल्टर हो गए और ब्याज बहुत ज्यादा हो गया। अब हमने ये तय किया है कि कर्जामाफी की झूठी घोषणा के कारण किसान के सिर पर जो ब्याज चढ़ गया है वो भाजपा की सरकार और मामा भरवाएगा।

छतरपुर में सबसे ज्यादा किसान डिफाल्टर

कमलनाथ सरकार गिरने तक 4 लाख 41 हजार 840 किसानों को कर्जमाफी योजना का लाभ न मिल पाने के चलते वे डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर हुए किसानों में सबसे 32 हजार 594 डिफाल्टर छतरपुर जिले में है और दूसरे नंबर पर मंदसौर में 26 हजार 431, दमोह में 20 हजार 871 किसान डिफाल्टर हैं। दस हजार से ज्यादा डिफाल्टर किसानों वाले जिलों में विदिशा, बैतूल, रायसेन, सीहोर, गुना, शिवपुरी, रतलाम, खंडवा, रीवा, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, सिवनी, बालाघाट और जबलपुर शामिल है।

किसानों को कर्ज से बचाने की कवायद

जय किसान ऋण माफी योजना का लाभ नहीं मिल पाने से कई किसान डिफाल्टर हो गए हैं। अब चुनाव करीब आते देख प्रदेश की भाजपा सरकार कमलनाथ सरकार की इस कमजोरी पर चुनावी दांव खेलने की तैयारी में है। कांग्रेस के कर्जमाफी की योजना के कारण डिफाल्टर हुए किसानों के साथ फसल ऋण जमा नहीं कर पाए सभी तरह के डिफाल्टर किसानों को बढ़ते ब्याज के बोझ से से मुक्त कर डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए ब्याज भरेगी।

कृषक ब्याजमाफी के दायरे में आएंगे

कर्जमाफी के चक्कर में करीब 4 लाख 41 हजार किसान डिफाल्टर हुए हैं। इनसे तीन गुना यानि 11 लाख से ज्यादा किसानों को ब्याजमाफी स्कीम के लिए चिन्हित किया है। इनके लिए शिवराज सरकार कृषक ब्याज सहायता योजना लाने की तैयारी में है। इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा संभवत: मई में सरकार इसकी घोषणा करेगी।

किसानों को तीन लाख तक का लोन

जिला सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक के जरिए किसानों को फसल के हिसाब से प्रति हेक्टेयर 50 हजार से सवा लाख रुपए तक का कर्ज बिना ब्याज पर मिलता है। कर्ज की अधिकतम सीमा तीन लाख रुपए तक होती है। इससे ज्यादा राशि का कर्ज बिना ब्याज नहीं मिल पाता। इस लिमिट में सभी छोटे-बड़े किसानों को ऋण की पात्रता होती है।

कैबिनेट की मंजूरी का हो रहा इंतजार

सरकार ने इस साल के बजट में 11 लाख डिफाल्टर किसानों की ब्याज माफी के लिए 27 सौ करोड़ का प्रावधान किया है। सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और वित्त विभाग मिलकर ब्याजमाफी का फार्मूला तय कर रहे है। कुल 11 लाख किसान इसके दायरे में आ रहे है। तय यह करना बाकी है दो लाख तक के मूलधन वाले किसानों को इसमें शामिल करना है या दो लाख तक मूलधन और ब्याज को मिलाकर इस दायरे में रखना है। या फिर जीरो प्रतिशत ब्याज दर की अधिकतम सीमा तीन लाख तक का कर्ज लेने वाले किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। ब्याजमाफी के फार्मूले पर मुहर लगते ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही लागू किया जाएगा।

डिफाल्टर किसान खाद बीज के लिए परेशान

बैंकों और सहकारी समितियों से डिफाल्टर हुए किसानों को खेती के समय पर सोसाइटियों से खाद, बीज नहीं मिल पाता। ऐसे में किसानों को मंहगे दामों पर खाद, बीज खरीदना पड़ता है। कई बार बीज और खाद की गुणवत्ता खराब होने पर किसान को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। अब सरकार किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिफाल्टर होने पर भी इसे मुहैया कराने की नीति पर भी विचार कर रही है।

मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम ने तकनीक को मप्र में लाने का निर्णय लिया

प्रदेश में पहली बार क्लोनिंग से पैदा होंगी ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस

भोपाल। जागत गांव हमार

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने क्लोनिंग के द्वारा मुर्रा नस्ल की भैंस के दो क्लोन पैदा करने में सफलता पाई है। अब मप्र राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम ने इस तकनीक को प्रदेश में लाने का निर्णय लिया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि यदि मुर्रा भैंस की क्लोनिंग होगी तो प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। भोपाल की मदरबुल फार्म स्थित आईवीएफ लैब में मुर्रा भैंस पैदा करने और देसी गाय की नस्ल सुधारने में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यह प्रदेश में इस तरह का पहला प्रयोग होगा। आईवीएफ लैब में एंब्रियो से होल्सटीन फ्रीजियन प्रजाति की गाय का एक बछड़ा पैदा किया जा चुका है। वहीं मप्र राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के एमडी डॉ. एसबीएस भदौरिया ने बताया कि एनडीआरआई में मुर्रा नस्ल की भैंस के दो नए क्लोन का जन्म 26 जनवरी 2022 को हुआ। मुर्रा भैंस की क्लोनिंग तकनीक से नस्ल सुधार कार्यक्रम को एक दिशा मिलेगी।

» आईवीएफ लैब में एंब्रियो से होल्सटीन फ्रीजियन प्रजाति की गाय का बछड़ा पैदा किया

» राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने दो क्लोन पैदा करने में सफलता पाई

हाइजेनिक मटेरियल के क्लोन

निगम के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) करनाल से जो तकनीक ली जा रही है। वह क्लोन बड़े हाइजेनिक मटेरियल वाले हैं। इस तकनीक से हूबहू बच्चे का जन्म होता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए अच्छी नस्ल और उच्च गुणवत्ता वाली भैंसों की तेजी से संख्या और दूध उत्पादन बढ़ाने में यह तकनीक मील का पत्थर साबित होगी।

दूनिया की सबसे ज्यादा दुधारू भैंस मुर्रा

मुर्रा भैंस की गिनती दुनिया की सबसे ज्यादा दुधारू भैंसों में होती है। एक मुर्रा भैंस एक दिन में 15-17 लीटर तक दूध देती है। ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है। गौरतलब है कि मदर बुल फार्म की आईवीएफ लैब में तैयार किए भ्रूण के प्रत्यारोपण से जनवरी 2023 को पहली बार बछड़ा पैदा हुआ था।

जिस भैंस का क्लोन करना है, उसकी कोशिकाओं को प्रयोगशाला में संवर्धन करते हैं। जो सेल संवर्धन किया उसका मिलाप स्लॉटर हाउस से प्राप्त ओवरी में केंद्रक रहित अंडाणु से करते हैं। इससे वह आठवें दिन भ्रूण बन जाता है। फिर भ्रूण को भैंस के गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, जिससे क्लोन बच्चे का जन्म होता है।

डॉ. आनंद सिंह कुशवाहा, आईवीएफ लैब इंचार्ज, मदर बुल फार्म, भोपाल

बांध की स्वीकृति पर विजयपुर क्षेत्र में छाई खुशी, भाजपा नेताओं ने बांटी मिठाई

चेटीखेड़ा बांध के लिए 539 करोड़ रुपए मंजूर, 55 गांव के किसानों को मिलेगा सिंचाई के लिए पानी

श्योपुर। जागत गांव हमार

विजयपुर की असिंचित जमीनों को सिंचित करने में सक्षम चेटीखेड़ा बांध को मध्यप्रदेश सरकार ने 539 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी भाजपा नेता अरविंद जादौन ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के माध्यम से दी। चेटीखेड़ा बांध की स्वीकृति मिलने पर भाजपा नेताओं ने गांधी चौक पर एकत्रित होकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में नारे लगाए और मिठाई बांटी।

विजयपुर से 20 किमी दूर क्वारी नदी पर बनने वाले चेटीखेड़ा बांध परियोजना नवंबर 2015 में अमल में लाई गई थी, जिसकी लागत इंजीनियर ने 346.25 करोड़ रुपए आंकी थी, इसके लिए अब सरकार ने मंगलवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में 539 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य हो कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 मार्च को श्योपुर में चेटीखेड़ा बांध को शीघ्र स्वीकृति देने की घोषणा की थी। यह प्रोजेक्ट विजयपुर की असिंचित भूमि को सिंचित करने के लिए अहम साबित होगा। जिसमें विजयपुर के 39 गांवों के अलावा मुरैना जिले के 16 गांवों की जमीनों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। बांध के पानी से 15 हजार 300 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी। अब तक विजयपुर क्षेत्र में सिंचाई के लिए नहर व बांध की व्यवस्था नहीं थी। जिससे किसान सीजन में कई फसलों की बोवनी नहीं कर पाते थे, लेकिन बांध बनने के बाद किसान सोयाबीन, धान सहित अन्य ज्यादा पानी लगने वाली फसलों की भी बुआई कर सकेंगे। बांध को बनाने के लिए सात गांवों की जमीनों का भी अधिग्रहण किया जाएगा।

इन गांवों की जमीन जाएगी बांध में

विजयपुर के चेटीखेड़ा बांध निजी 674.376 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इनमें विजयपुर का रनसिंहपुरा, चेटीखेड़ा, अरोंद, शाहपुरा, घोरदेह, देहरी और अगरा गांव शामिल है। जिसमें रनसिंहपुरा की 40.29, चेटीखेड़ा की 235.40, अरोंद की 167.214, शाहपुरा की 50.313, घोरदेह की 5.892, देहरी की 1.023 और अगरा की 174.235 हेक्टेयर भूमि बांध बनाने के लिए अधिग्रहण की जाएगी। इसके अलावा बांध निर्माण में राजस्व की 476.524 हेक्टेयर व वन विभाग की 69 हेक्टेयर भूमि चली जाएगी।

21.32 किमी लंबी होगी नहर

चेटीखेड़ा बांध के बनने के साथ इसमें से नहर भी निकाली जाएगी। जिसमें एक दाय और तो दूसरी बाय गांवों में पानी पहुंचाएगी। 346 करोड़ 25 लाख की लागत से बन रहे बांध में दायी और 6.84 किमी लंबी नहर बनाई जाएगी। जबकि बायी और 21.32 किमी लंबी नहर का निर्माण कराया जाएगा, जो बांध में भरने वाले पानी को गांवों तक पहुंचाएगी।

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मांग पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में चेटीखेड़ा बांध के लिए 539 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। चेटीखेड़ा बांध किसानों की तकदीर बदलने का काम करेगा।
अरविंद सिंह जादौन
जिला महामंत्री, भाजपा

रंग लाई विधायक शरद, कलेक्टर, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की मेहनत, 79 गांवों के 26 हजार किसानों को मिलेगा लाभ

ब्यौहारी के किसानों की तकदीर बदल देगी हिरवार-भन्नी सिंचाई परियोजना

भारत एक कृषि प्रधान देश है यदि किसानों को पर्याप्त सिंचाई आदि की सुविधाएं सरलता से मुहैया हो जाएंगी तो उन्हें इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि किसान ही अन्नदाता है। आदिवासी प्रधान इस अंचल के दर्शकों को जल संसाधन विभाग द्वारा उत्तरोत्तर बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। परियोजना के लिए जल का उपयोग बाणसागर बहुउद्देशीय व्रत परियोजना से किया जाना है बाणसागर परियोजना के डूब क्षेत्र से 60 क्यूमेक पानी उस भयंकर पाइप वितरण प्रणाली द्वारा कृषकों के खेत में अंतिम छोर पर 20 मीटर हेड से स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई की जाने की योजना का निर्माण कार्य मार्च 2026 में पूर्ण कराया जाना प्रचलित है। जिले के विकासखंड ब्यौहारी अंतर्गत जिले की प्रथम मध्यम सिंचाई योजना हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना तथा भन्नी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना क्षेत्र के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल देगी।

शहडोल। जागत गांव हमार

पांच अप्रैल 2023 का दिन इस क्षेत्र के लोगों के लिए खास तौर पर ब्यौहारी के किसानों के लिए सौभाग्यशाली दिन साबित हुआ है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा तेंदूपत्ता बोनस वितरण, पेसा एक्ट के तहत लोगों को लाभान्वित किया गया।

परियोजना मील का पत्थर

मुख्यमंत्री द्वारा शहडोल जिले के विख ब्यौहारी अंतर्गत जिले की प्रथम मध्यम सिंचाई योजना हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा 1 जून 2017 द्वारा 116, 78 करोड़ की राशि प्रदान की गई ।

हिरवार परियोजना

हिरवार परियोजना से 37 ग्रामों के लगभग 6000 कृषकों को 7481 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, परियोजना के निर्माण के लिए में मेसर्स फलोदी कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इंदौर द्वारा रुपए 106,42 करोड़ का अनुबंध 02 अगस्त 2018 को हस्ताक्षरित किया गया है। निर्माण कार्य जून 2022 में पूर्ण किया गया। परियोजना के लिए जल का उपयोग बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना से किया जाना है।

इन गांवों के किसानों को मिलेगा लाभ

परियोजना के निर्माण से विकासखंड व्यहारी के 37 ग्राम जमुनी1 व 2, सरसी,चितरासी, पथरेही, हिनौता, निपनिया ,टीकुरा टोला, निपनिया 339,टिकरा टोला दो, बहेरिया खड़ेह, कुआं एक, मरतला, सकन्दी,उजरवरा,,बिलकुड़ा एवं घीनोदी, दलको कोठार2, एवं दलको जागीर ,हिरवार एक, दलको कोठार दो,हिरवार दो ,रेउसा, बरा बघेलहा,पापोन्ध एक, पोड़ी खुर्द, पापोन्ध 2, तेंदुहा, उमरगढ़ , शिलबा कछार ,ओदारी, पापोन्ध3, लालपुर, ओदारी,प?री, निपनिया तीन, कुआं2, कुआं तीन लाभान्वित होंगे।

परियोजना की विशेषताएं

प्रशासकीय स्वीकृति 116,78 करोड़, निविदा राशि 113,53 करोड़, अनुबंधित राशि 106,415 करोड़, टंकी में पानी की ऊंचाई 4,75 मीटर, बीपीटी की क्षमता 630 मीटर, पानी का उठाव 79, 00 मीटर, कुल प्रदाय क्षमता 3,15 घन मीटर /सेकंड ,1408 पावर के पंपों की संख्या 3 प्लस 1 रिजर्व, पाइप में जल का वेग 2.045 मीटर/ सेकंड ,वर्ष में कुल जल आवश्यकता 36,00 एमसीएम, प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 7481,00 हेक्टेयर, विद्युत आवश्यकता 3,50 मेगावाट।

भन्नी परियोजना का संक्षिप्त विवरण

जिले के विकासखंड ब्यौहारी अंतर्गत भन्नी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए में, विजय कुमार मिश्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड रीवा एवं भैयालाल इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम द्वारा रुपए 327, 51 करोड़ का अनुबंध 03 मार्च 2023 को हस्ताक्षरित किया गया है। 42 ग्राम के लगभग 20,000 कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

ग्रामों के किसानों को मिलेगा लाभ

जानकारी के मुताबिक ग्राम सेजहरी, करौंदिया, गाड़ा, नकुनी, भमरहा द्वितीय,भन्नी, देवरी, मऊ, खांमडार, चरखरी, धमदरी, भेलबहरा, खरपा, देवराव, पसगड़ी, सरवाही खुर्द, पपरेड़ी, बोड्डीहां, कलहारी,खुटेहरा, मुदरिया, छिराहा, सूखा, खड़हुली, साखी, ब्यौहारी, बरहाटोला, विजहा, आखेटपुर, मेरट्रोला ,देवगवा, तेंदुहा,उकसा, रसपुर, झरोसी, भमरहा प्रथम ,बराछ, खड्डा, सन्नोसी, पुरैना, बलौड़ी पश्चिम लाभान्वित होंगे।

भन्नी परियोजनाः प्रमुख विशेषताएं

परियोजना की अनुमानित राशि 327,51 करोड़, कार्य पूर्णता की संभावित तिथि मार्च 2026, टंकी में पानी की ऊंचाई 05 मीटर, बीपीटी की क्षमता 1152 किली, पानी का उठाव 93,00 मीटर, कुल प्रदाय क्षमता 6,41 घन मीटर/ सेकंड,, 2000 हॉर्स पावर के पंपों की संख्या 4 प्लस 1 रिजर्व, पाइप में जल का बैग 1,75 मी. /सेकंड,, वर्ष में कुल जल आवश्यकता 56,00 एमसीएम, ग्रेविटी मैन की कुल लंबाई 26 किलोमीटर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की लंबाई 420 किलोमीटर ,प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 18300 हेक्टेयर विद्युत आवश्यकता 7,64 मेगा वाट।

केंद्र ने दी दस प्रतिशत तक गेहूं खरीदने की अनुमति

अधिक होने पर प्रति क्विंटल पांच रुपए काटेगा केंद्र

किसानों का चमक विहीन गेहूं भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दस प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं भी खरीदने का निर्णय लिया है। ओलावृष्टि और वर्षा के कारण गेहूं की चमक चली गई है। इसके कारण किसान चिंतित हैं कि यदि सरकार ने समर्थन मूल्य पर यह उपज नहीं ली तो फिर उन्हें मंडियों में औने-पौने दाम पर इसे बेचना होगा। इसे देखते हुए राज्य सरकार के केंद्र से आग्रह किया था कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए विशेष छूट दी जाए, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। यह भी तय किया गया है कि दस प्रतिशत से अधिक चमकविहीन गेहूं यदि सरकार ने खरीदा तब प्रति क्विंटल पांच रुपए 31 पैसे की कटौती केंद्र सरकार करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने यह रास्ता निकाला है कि इसकी भरपाई राज्य सरकार खुद करेगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में सभी मंत्रियों को दी।

15 लाख 20 हजार पंजीयन

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 15 लाख 20 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रति क्विंटल दो हजार 125 रुपए की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। इसके लिए चार हजार 200 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं और खरीदी का काम पूरे प्रदेश में प्रारंभ भी हो गया है। इस बार ओलावृष्टि और वर्षा के कारण गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। दानों की चमक चली गई है। सामान्यत: समर्थन मूल्य पर इस तरह का गेहूं नहीं खरीदा जाता है लेकिन किसान हित को देखते हुए शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि चमकविहीन गेहूं के उपार्जन की अनुमति दी जाए।

गेहूं सशर्त लिया जाएगा

केंद्र सरकार ने राज्य के प्रस्ताव को मान्य करते हुए सामान्य तौर पर 10 प्रतिशत चमक विहीन गेहूं खरीदने की अनुमति दे दी। साथ ही यह छूट भी दी है कि दस से अस्सी प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं भी सशर्त लिया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार प्रति क्विंटल पांच रुपये 31 पैसे काटेगी। दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार केंद्र के लिए विकेंद्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत उपार्जन कराता है। इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार देती है। इस बार 80 लाख टन गेहूं के उपार्जन के हिसाब से तैयारी की गई है।

मिलेगी राहत

सीएम ने बताया कि ओलावृष्टि और वर्षा से प्रभावित फसलों का आकलन कार्य शीघ्र ही पूरा कराकर राहत राशि वितरित की जाएगी। इसमें प्रति हेक्टेयर 32 हजार के हिसाब से राहत राशि दी जाएगी। अभी तक 72 हजार हेक्टेयर में फसलें प्रभावित होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कुछ जिलों से जानकारी आना बाकी है। इसके साथ ही किसानों को फसल बीमा की राशि भी दिलवाई जाएगी। इसके लिए बीमा कंपनियों को अपनी कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

सीएम बोले- 50 फीसदी नुकसान पर देंगे 32 हजार हेक्टेयर

70 हजार हेक्टेयर में फसल बर्बाद प्रदेश के पांच जिलों का सर्वे बाकी

सीएम ने मंत्रियों को कहा कि गेंहू खरीदी प्रारंभ हो रही है। सीएम ने कहा कि अभी 70 हजार हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है। वहीं, 64 करोड़ की राहत राशि अभी तक आ रही है। अभी चार से पांच जिलों का सर्वे पूरा नहीं हो पाया है। सीएम ने मंत्रियों से कहा कि आप भी चेक कर लें। हम कोशिश करेंगे सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी जिलों में एक साथ राशि डाल दें। आरबीसी 6-4 में 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान होने पर 32 हजार प्रति हेक्टेयर देना तय किया है। फसल बीमा योजना का लाभ भी हम अपने किसानों को देंगे। सरकार चमक विहिन गेंहू भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। खाद का एडवांस उठाव होगा।

शिवराज ने जारी किया टोल फ्री नंबर

मप्र में पशुओं के लिए अब चलेगी एंबुलेंस

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में पहुंचे। जहां उन्होंने नर्मदा उद्गम स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री जैन मुनि श्री आचार्य विद्यासागर महाराज से मुलाकात की और उसके बाद आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया गौ सेवा सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने सर्वोदय तीर्थ पंचकल्याण मंदिर पहुंचकर भगवान आदिनाथ के दर्शन कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सर्वोदय तीर्थ पंचकल्याण मंदिर के संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की तथा वहां एक हजार स्थापित किए गए प्रतिमाओं के संबंध में भी जानकारी ली। अमरकंटक में आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया गौसेवा सम्मान योजना पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पशुओं के लिए एंबुलेंस नंबर जारी किया। इसमें गौ-माता और अन्य पशुओं के लिए एमपी में एंबुलेंस की व्यवस्था 1 महीने के अंदर की जाएगी। पशु सेवा एंबुलेंस टोल फ्री नंबर 1962 एक महीने में शुरू हो जाएंगे।

हर ब्लॉक को सौगात

आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया सम्मान योजना के दौरान सीएम शिवराज ने घोषणा की है कि अब मवेशियों के लिए एंबुलेंस की निःशुल्क सेवा शुरू की जा रही है। हर ब्लॉक में एक एंबुलेंस दी जाएगी। 460 एंबुलेंस पूरे प्रदेश भर में घायल मवेशियों के उपचार के लिए उपलब्ध होंगी। इस एंबुलेंस में एक डाक्टर, कंपाउंडर भी मौजूद रहेगा।

साल 2011 में 224 रह गए थे, इस साल की गणना में 740 इंडियन स्कीमर गिने गए

चंबल नदी में एक साल में बढ़े 240 इंडियन स्कीमर, 2022 की गणना में मिले थे 500

मुरैना। घड़ियालों के लिए पहचानी जाने वाली चंबल नदी और उसके बीहड़ विलुप्तप्राय प्रजाति के इंडियन स्कीमर पक्षियों की वंशवृद्धि के लिए स्वर्ग साबित हो रहे हैं। नदी के साफ पानी और बीहड़ में सुरक्षित रहवास के कारण बीते एक साल में नदी किनारों पर इंडियन स्कीमर के कुनबे में 240 नए मेहमान आए हैं। चंबल घड़ियाल अभयारण्य में 2022 की गणना अनुसार 500 इंडियन स्कीमर थे। इस साल इनकी संख्या 740 हो गई है। वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 1994 में सर्वाधिक 554 इंडियन स्कीमर थे, इसके बाद यह लगातार कम होते रहे और साल 2011 में संख्या मात्र 224 रह गई थी। चंबल नदी में हर साल कई प्रवासी पक्षी सर्दी के सीजन में रहते हैं और प्रजनन के बाद बच्चों सहित अपने देश लौट जाते हैं। इन्हीं प्रवासी पक्षियों में से एक इंडियन स्कीमर है। गुलाबी लंबी चोंच, सफेद गर्दन, काले रंग का धड़ और गुलाबी पैरों वाले इस पक्षी को पनचीरा भी कहा जाता है, क्योंकि यह उड़ते हुए ही चोंच से पानी को चीरते हुए मछली का शिकार करता है।

2018 से चल रहा संरक्षण का काम

पक्षियों के संरक्षण का काम करने वाली संस्था बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी साल 2018 से शिकारी पक्षी, सर्प व अन्य जानवरों से इंडियन स्कीमर के अंडों की रखवाली करने का काम करती आ रही है। ये पक्षी साफ पानी के किनारे, गीले व भरपूर नमी वाले रेत के टापुओं पर वंशवृद्धि करते हैं।

नदी के तटों पर बसेरा

इंडियन स्कीमर नवंबर से जुलाई तक चंबल नदी व उसके तटों पर बसेरा करते हैं। मार्च से मई तक इनका प्रजनन काल होता है। जुलाई-अगस्त में जब बच्चे उड़ान भरने में परिपक्व हो जाते हैं और बारिश होने के कारण चंबल के टापू पर बने इनके बसेरे डूब जाते हैं तो यह पक्षी गुजरात के जाम नगर से लेकर, आंध्रप्रदेश के काडीनाडा, पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार (वर्मा) तक पहुंच जाते हैं, वहां मानसून सीजन बीतने के बाद चंबल में लौट आते हैं।

हमने इंडियन स्कीमर पक्षियों के अंडों की रखवाली के लिए विशेष इंतजाम किए। चंबल का पानी स्वच्छ है, जिसमें किसी भी तरह का केमिकल या फर्टिलाइजर मौजूद नहीं है। चंबल के रेतीले टापू, सुरक्षित रहवास व भरपूर शिकार है, इसलिए यहां इंडियन स्कीमर की संख्या लगातार बढ़ रही है।

स्वरूप दीक्षित, डीएफओ, चंबल घड़ियाल अभयारण्य

पूरे देश में ऐसा स्थान केवल चंबल नदी है, इसीलिए पूरी दुनिया में इंडियन स्कीमर की 80 फीसद आबादी चंबल नदी के तटों व टापुओं पर पाई जाती है। यह पक्षी भी नदी को स्वच्छ रखते हैं, क्योंकि विशेषकर यह ऐसी मछलियों का शिकार करते हैं, जो पानी में गंदगी बढ़ाती हैं।

परवीन खान, सदस्य, बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी

प्राकृतिक कृषिः ग्रामीण आय स्थिरता हेतु एक उत्कृष्ट समाधान

डॉ. आनंद प्रकाश शुक्ला

प्राकृतिक खेती पारंपरिक भारतीय पद्धतियों से उद्धृत रासायनिक मुक्त कृषि की एक विधि है। यह एक अनूठा मॉडल है जो कृषि-पारिस्थितिकी पर निर्भर करता है। इसका उद्देश्य उत्पादन की लागत को कम करना और एक स्थायी स्तर पर वापसी को बढ़ावा देना है। इस कृषि के संदर्भ में यह दावा किया जाता है कि इसमे उर्वरक, कीटनाशक और गहन सिंचाई जैसे महंगे इनपुट की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक खेती मिट्टी की सतह पर सूक्ष्मजीवों और केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के विखंडन को प्रोत्साहित करती है, धीरे-धीरे समय के साथ मिट्टी में पोषक तत्वों को जोड़ती है। हालांकि, जैविक खेती में, जैविक खाद और खाद, जैसे खाद, वर्मी-कम्पोस्ट, और गाय के गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है तथा इन्हे कल्टिवेटेड खेत में प्रयोग किया जाता है।

जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के स्तम्भः जीवामृत गाय के गोबर और मूत्र (देसी नस्लों के), गुड़, दालों के आटे, पानी और खेत के बांध से मिट्टी का किण्वित मिश्रण है। यह उर्वरक नहीं है बल्कि यह लगभग 500 करोड़ सूक्ष्म जीवों का एक स्रोत है। इसके द्वारा सभी आवश्यक गैर-उपलब्ध पोषक तत्वों को उपलब्ध रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।

बीजामृत देसी गाय के गोबर और मूत्र, पानी, बांध मिट्टी और चूने का मिश्रण है जिसे बुवाई से पहले बीज उपचार समाधान के रूप में उपयोग किया जाता है।

मल्चिंग, या सूखे भूसे या गिरे हुए पत्तों की एक परत के साथ पौधों को ढंकना, मिट्टी की नमी को संरक्षित करने और जड़ों के आसपास के तापमान को 25-32 डिग्री सेल्सियस पर रखने के लिए है। यह सूक्ष्मजीवों की क्रियाविधि को संचालित करता है।

वाफासा, (आवश्यक नमी) वायु संतुलन बनाए रखने के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूर्ण करता है।

एपीडा के ट्रेसनेट सर्टिफिकेशन सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुशल उपयोग के लिए व्यापक और अभ्यास करने

वाले किसान शामिल हैं।

साथ ही प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादित फसलों के लिए मानक विकसित किए जाएंगे और जैविक उत्पादों से अलग निर्यातोन्मुख ब्रांडिंग के साथ प्रचार शुरू किया जाएगा। प्राकृतिक खेती की उपज के लिए प्रीमियम प्राप्त करने के लिए विपणन बहुत महत्वपूर्ण है जो कि किसानों के लिए प्रमुख प्रेरकों में से एक होगा।

आत्मनिर्भर भारत के लिए किसी भी परिदृश्य में खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर, सरकार ने कहा कि ऐसा कोई खतरा नहीं है क्योंकि प्राकृतिक खेती में उत्पादन में गिरावट नहीं होगी। इसके साथ ही साथ तिलहन और दलहन जैसी फसलों का चयन देश के लिए फायदेमंद होगा। वर्तमान बीपीकेपी योजना सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों के बहिष्कार पर जोर देती है और बायोमास मल्चिंग, गाय के गोबर-मूत्र फॉर्मूलेशन के उपयोग और पौधों पर आधारित तैयारियों पर प्रमुख तनाव के साथ ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है, जो किसानों को कृषि उत्पादकता और आय स्थिरता को बढ़ाती है।

नीति कार्यान्वयन में सरकारी आवंटन बढ़ाना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना: आरकेवीवाई के तहत आवंटन को मौजूदा वित्त वर्ष में 3,712.44 करोड़ रुपए (बीई) से 2022-23 के लिए लगभग तीन गुना बढ़ाकर 10,433 करोड़ रुपए कर दिया गया है और यह वृद्धि संशोधित अनुमान से पांच गुना अधिक है।

यह योजना राज्यों को अपनी स्वयं की योजनाओं को विकसित करने और कार्यान्वित करने और केंद्रीय निधियों को आकर्षित करने के लिए नम्यता की अनुमति देती है। प्राकृतिक खेती पर संशोधित योजना राज्यों को आरकेवीवाई बजट से केंद्रीय सहायता से अधिक अतिरिक्त धनराशि वितरित करने की अनुमति भी दे सकती है। कृषि मंत्रालय की योजना योगिक खेती, गौमाताखेती और ऋषि कृषि करने वाले किसानों को नकद प्रोत्साहन देने की है जो भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सही कदम है। इसके साथ ही उचित संस्थागत तंत्र और कृषि विस्तार सुविधाओं जैसे ब्रांडिंग, प्रमाणन और विपणन को विकसित करने की आवश्यकता है जिससे आय स्थिरता और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

सालाना 50 फीसदी की दर से नष्ट हो रहे हैं पहाड़ी जंगल, खतरे में जैव विविधता

दुनिया के 85 फीसदी से अधिक पक्षी, स्तनपायी और उभयचर प्रजातियां पहाड़ी जंगलों में रहते हैं, लेकिन ये जंगल तेजी से गायब हो रहे हैं। अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में, 2000 के बाद से 7.81 करोड़ हेक्टेयर यानी 7.1 फीसदी पहाड़ी जंगल गायब हो गए हैं। अधिकांश नुकसान उष्णकटिबंधीय जैव विविधता हॉटस्पॉट में हुआ है, जिससे संकटग्रस्त प्रजातियों पर दबाव बढ़ रहा है। 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से इन पहाड़ी जंगलों का तेजी से शोषण किया गया है क्योंकि तराई क्षेत्र कम हो गए हैं या संरक्षण के अधीन हैं। यह अध्ययन यूके में लीड्स विश्वविद्यालय के डोमिनिक स्पैकलेन और जोसेफ होल्डन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम और चीन में दक्षिणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया है। जहां शोधकर्ताओं ने झेनझोंग ज़ेंग पर्वत पर जंगलों के नुकसान की सीमा और वैश्विक वितरण का पता लगाया है। ऐसा करने के लिए, टीम ने 2001 से 2018 तक हर एक साल के आधार पर पहाड़ के जंगलों में होने वाले बदलाव पर नजर रखी। उन्होंने पेड़ों के आवरण में नुकसान और बढ़ोतरी दोनों की मात्रा निर्धारित की, अनुमान लगाया कि किस दर पर बदलाव हो रहा है, विभिन्न ऊंचाई और पहाड़ी जंगलों के प्रकारों की तुलना में बोरियल, समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय और जैव विविधता पर इस जंगलों के नुकसान के प्रभावों का पता लगाया।

अध्ययनकर्ता कहते हैं, दुनिया भर में ऊंचाई वाले ग्रेडियेंट के साथ जंगलों के नुकसान की गति की जानकारी यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि पेड़ों की प्रजातियों के लिए उपलब्ध जंगली इलाकों की मात्रा कैसे और कहां बदल जाएगी, क्योंकि वे बढ़ते तापमान के जवाब में बदल जाएंगे।

इमारती लकड़ी उद्योग से समग्र रूप से पहाड़ों में होने वाले जंगलों का नुकसान का सबसे बड़ा कारण था, यह 42 फीसदी तक देखा गया। इसके बाद जंगल की आग जिसका हिस्सा 29 फीसदी, खेती के लिए जंगल में आग लगा देना जो 15 फीसदी और स्थायी या अर्ध-स्थायी कृषि 10 फीसदी तक के लिए जिम्मेवार पाई गई थी। हालांकि इन विभिन्न कारणों का असर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग-अलग होता है। एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भारी नुकसान हुआ, लेकिन उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में ऐसा नहीं है। यह काफी चिंताजनक है कि पर्वतीय पेड़ों के नुकसान की दर में तेजी आ रही है, 2001 से 2009 और 2010 से 2018 तक नुकसान की वार्षिक दर में 50 फीसदी की वृद्धि हुई, जब हमने हर एक साल लगभग 52 लाख हेक्टेयर पर्वतीय वनों को खो दिया। अध्ययनकर्ता कहते हैं कि यह हो सकता है मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से कृषि विस्तार के कारण ऐसा हो रहा है। साथ ही पहाड़ी जंगलों के काटे जाने में वृद्धि के कारण या तो तराई के जंगलों की कमी हो गई है, या तराई के जंगल संरक्षित हो गए हैं।

उष्णकटिबंधीय पहाड़ी जंगलों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जो कि दुनिया भर के पूरे का 42 फीसदी और सबसे तेज दर है। लेकिन समशीतोष्ण और बोरियल क्षेत्रों में पहाड़ के जंगलों की तुलना में तेजी से बढ़ने की दर भी देखी गई।

तत्व आहारीय खनिजः सूकरों के लिए एक आवश्यक पोषक

» डॉ. निर्मला मुवेल
» डॉ. सुनील नायक
» डॉ. अंकुर खरे
» डॉ. राहुल शर्मा
» डॉ. अंचल केशरी
» डॉ. रूपेश वर्मा
» डॉ. पंकज चौबे

सहायक प्राध्यापक, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर, मप्र

सुकरपालन का मुख्य आधार स्तम्भ है संतुलित आहार, जिसमें विभिन्न आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजुद होते हैं। इनमें खनिज-लवण सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं ये आहार के द्वारा शरीर को मिलते हैं एवं पोषण करने में सहायक होते हैं। इसीलिए इन्हें आहारीय खनिज कहते है। खनिज लवणों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। मेजर खनिज लवण: ये तत्व अत्यावश्यक होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नेशियम, पोटाशियम, सोडियम, सल्फर और क्लोरीन अत्यावश्क हैं। माइनर खनिज लवण सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक हैं। तांबा, आयोडिन, लोहा, जस्ता, मैगनीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम और मोलिब्डेनम।

सूकरों में खनिज तत्वों का महत्व: सूकरों में 3-5 प्रतिशत खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत करने, तंतुओं का विकास करने में मेटाबोलिज्म को विघटित करने, पाचन शक्ति बढ़ाने, खून बनाने, दूध उत्पादन, प्रजनन एवं स्वास्थय के लिए आवश्यक हैं। पशुओं के शरीर में सामान्यता सभी खनिज तत्व होते हैं। अभी तक पशु आहार में 22 खनीज लवणों के महत्व की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। कैलसियम, फास्फोरस, मैगनिशियम, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, आयरन, तांबा, जिंग, मैगनीज, कोबाल्ट, आयोडिन जैसे खनिज लवण पशुओं के लिए आवश्यक खनिज लवण होते हैं। आमतोर से ये तत्व पशुओं को आहार से प्राप्त हो जाते हैं। ये आवश्यक तत्व सभी आहार में होते हैं लेकिन इनका अनुपात कम मात्रा में होता है। सही मात्रा में खनिज तत्व देने से पशु स्वस्थ रहते हैं और उनमें बढ़ोत्तरी सामान्य होती है। उत्पादन सामान्य रहता है। खनिज मिश्रण व नमक से इन तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। खनिज तत्वों के स्त्रोत और खिलाने की विधि: चोकर, चावल की भूसी से फास्फोरस मिल जाता है।

खनिज लवण खिलाने से लाभ: उच्च गुणवत्ता तथा सही मात्रा में खनिज लवण खिलाने से कई लाभ होते हैं उनमें से कुछ मुख्य लाभ नीचे इंगित किये गये हैं:-

1. दुग्ध व मांस उत्पादन में वृद्धि। 2. नर और मादा पशुओं की प्रजनन क्षमता में सुधार। 3. बच्चो की शारीरिक विकास दर में सुधार, जिससे वे शीघ्र वयस्क होते हैं। 4. दो ब्यातों के बीच समयावधि में कमी। 5. पशु आहार उपभोग एवं पाचन क्रिया में सुधार। 6. बेहतर शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता । 7. स्वस्थ सबल बच्चो का जन्म। 8. पशुओं के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार। 9. क्षेत्र विशेष का खनिज लवण खिलाने पर कम खर्च और अधिक प्रभावी।

खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग:

कैल्शियम: यह शरीर में पाए जाने वाले सभी खनिज तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है यह हड्डियों व दांतो के निर्माण व वृद्धि में सहायक होता है। बढ़ते सूकरों में कैल्शियम या फास्फोरस की कमी से रिकेट्स और परिपक्व सूकरों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। बच्चों के पैरों में विकृति, चाल में कड़ापन, पैरों के जोडों में सूजन आ जाना तथा कड़ापन उभरना, इसके दृष्टिगत लक्षण हैं। यह ज्यादातर अगले पैरों मे के जोड़ों में होता है। चाल में लंगड़ापन के साथ पशुओं में ज्यादा बैठने की आदत विकसित हो जाती है। कमर से पशु झुक जाता है तथा अस्थि भंग होने की सम्भावना ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा दांत भी देर से निकलते हैं तथा कैलसियम की कमी से टेढ़े-मेढ़े, छोटे गड्ढे तथा दांतों पर मटमैला रंग आ सकता है। दांतों के साथ ही जबड़ों की हड्डी मुलायम तथा

मोटी हो जाती है।

अस्थि मृदुता: ओस्टोमलशिया, रोग कैलशियम की कमी से बड़ी उम्र क पशुओं में होती है। इसमें वयस्क सुकरो में फ्रैक्चर और काठ का क्षेत्र में पश्च पक्षाघात के लक्षण दिखाई देते हैं। यह बीमारी गर्भवती मादाओं या अधिक दुध देने वाली मादाओं में ज्यादा होती है। जब पशु को प्र्याप्त मात्रा में कैल्शियम तथा फास्फोरस आहार से नहीं मिल पाता है तो गर्भ में विकसित होने वाले भ्रूण तथा दूध देने वाले पशुओं में रक्त में यह तत्व हड्डियों से आते हैं, जिससे कि हड्डी कमजोर होने लगती है। अस्थि संरचना का कार्य कम हो जाता हे तथ रोग ग्रस्त पशुओं की हड्डी आसानी से टूट जाती है। पशु की चाल में कड़ापन आने लगता है। पशु के जबड़ों में सूजन दिखाई देने लगती है। कैलशियम एवं फासफोरस की कमी से पशुओं की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है एवं मादा बांझपन का विकार हो जाती है। रिकेट्स तथा ओस्टोमलेशिया रोगों के उपचार तथा रोगथाम के लिए पशुओं को उचित मात्रा में कैलशियम तथा फास्फोरस देना चाहिए।

फास्फोरस: फास्फोरस भी कैलशियम के साथ हड्डियों तथा दॉतों के लिए बहुत आवशयक अवयव है। डीएनए व आरएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फॉस्फोरस की कमी से पाइका रोग होता है इस रोग मे पशु मिटटी, हड्डी, कपडे, पॉलीथिन जैसी न खाने योग्य वस्तुएं खाने लगता है।

आयोडीन: आयोडीन थायरोक्सिन हॉर्मोन के निर्माण में सहायक होता है व शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। ये हार्मोन चपायचयी क्रियाओं, शारीरिक वृद्धि, दूध उत्पादन और अस्थि विकास में सक्रिय भाग लेते हैं। आयोडीन हीनता के कारण थायरायड और अन्य हार्मोनों की पूर्ति हेतु थायरायड ग्रंथी का आकार कई गुना बढ़कर गले के बाहर निकल आता है, जिसे घेंघा या गलघोंटू कहते हैं। आयोडीन की कमी से पशुओं की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। प्रजनन संबंधी विकृतियां उत्पन्न होती हैं। आयोडीन की कमी से बाल रहित सूअर पैदा होते हैं, जो कमजोर या मृत पैदा होते हैं।

आयरन: आयरन हीमोग्लोबिन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व शरीर में ऑक्सीजन परिवहन कराता है साथ ही त्वचा में मिलेनिन निर्माण में भी सहायक होता है। शरीर में आयरन की कमी से अल्परक्तता (एनीमिया), शारीरक वृद्धि में गिरावट तथा अल्परक्तता के कारण मृत्य तक हो जाती है। जन्म के बाद 2 से 4 सप्ताह के बच्चों के लिए ये अल्परक्तता (एनीमिया) घातक होती है इसीलिए छोटे बच्चो को 7 से 16 मि. ग्रा. आयरन प्रतिदिन खिलाना चाहिए। शरीर में तांबे की कमी से भी अल्परक्तता हो जाती है।

जस्ता: जस्ता शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों को चलाने के लिए आवश्यकता होती है। जस्ता के कमी से पशुओं में पैराकिरोटोसिस रोग हो जाता है। इस रोग में त्वचा पर चकते, सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते है। पैराकिरेटिस के कारण पैरो के जोड़ों में दर्द होता है और पशुओं के चाल में अकड़न आ जाती है। दुधारू मादाओं में दूध उत्पादन घट जाता है तथा प्रजनन सम्बन्धी विकृतियाँ जैसे अनिच्छित मदकाल, जेर अवरोध तथा दुर्बल बच्चों का जन्म होता है। पशुओं में शारीरिक वृद्धि दर घटने लगती

महिलाओं का हुआ सम्मान महिलाओं का हुआ सम्मान सम्मान महिलाओं

मशरूम उत्पादन से महिलाओं की सुधरी सेहत, बढ़ी आमदनी और आत्मनिर्भरता

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के द्वारा जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए क्षमता वर्धक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं मैं रोजगार के अवसर, कुपोषण दूर करना एवं महिलाओं को श्रम शक्ति का खेती से अधिक क्षमतावान बनाने के लिए प्रशिक्षण किए जा रहे हैं। मशरूम उत्पादन के लिए जिले में अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए मशरूम उत्पादन पर क्षमता वर्धक प्रशिक्षण रजनी ननोटकर अंबेडकर नगर टीकमगढ़ द्वारा लेकर मशरूम उत्पादन के कार्य को 2021 से प्रारंभ किया था। इसके बाद ननोटकर द्वारा महिलाओं में मशरूम उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एक बुंदेलखंड महिला मशरूम उत्पादक स्वा-सहायता समूह का गठन किया गया, जिसमें 10 महिलाएं इस मशरूम उत्पादन में कार्य करने लगी इसके बाद मशरूम उत्पादन के सह-उत्पाद जैसे-आचार, चटनी, पापड़, बड़ी, के साथ साथ अन्य बनाने का कार्य किया गया। टीकमगढ़ जिले में अब ऑयस्टर मशरूम के साथ साथ दूधिया एवं बटन मशरूम का उत्पादन बढ़ने लगा, हमारी एकता महिला मशरूम उत्पादक स्वा-सहायता समूह मऊ चुंगी एवं रौनक मशरूम फार्म जैसे समूह आज जिले मैं मशरूम से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं एवं रोजगार के अवसर एवं महिलाओं में उत्तम स्वास्थ्य, अधिक आमदनी एवं आत्म निर्भरता बनाने में कारगर साबित हो रहा है। रजनी ननोटकर द्वारा गांवों-गांवों में मशरूम उत्पादन जागरूकता एवं प्रसार किया जा रहा है।

राज्यपाल द्वारा दिया गया पुरस्कार और प्रशस्तिपत्र

रजनी ननोटकर को माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश द्वारा भी इस वर्ष पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा सुषमा स्वराज अवार्ड कार्यक्रम कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर की ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कार्यरत रहते हुए देश एवं प्रदेश स्तर पर अपना नाम रोशन किया है, उन्हें सम्मानित किया गया। ननोटकर को महिलाओं में मशरूम उत्पादन स्वयं करके एवं अन्य महिलाओं को जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें सुषमा स्वराज अवार्ड एवं प्रशस्ति पत्र से वर्ष 2023 के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष नंदिता पाठक एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला अध्यक्ष अमित नुना जी, टीकमगढ़ विधायक माननीय राकेश गिरी गोस्वामी जी एवं अन्य गणमान्य एवं भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे । डॉ. बीएस किरार प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के नेतृत्व में मशरूम उत्पादन के लिए रणनीति बनाकर जिले में डॉ. आरके प्रजापति द्वारा मशरूम प्रशिक्षण प्रभारी के रूप में कार्य किया जा रहा है।

अब बालाघाट में होगी मखाना की खेती

दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र में 20 किसानों ने लिया प्रशिक्षण

बालाघाट। चिन्नोर चावल को मिले जीआई टैग से विश्व में पहचान बनाने बाले चिन्नोर चावल के बाद जिले के कृषक मखाने की खेती में भविष्य देखने ग्यारह सौ किमी दूर बिहार के दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र पहुंचे। बालाघाट क्षेत्र के धान खेतों की संरचना जैसे खेतों में मखाने का उत्पादन लिया जा सकता है, यहां की मिट्टी, जलवायु मखाना उत्पादन के लिए अनुकूल है। परियोजना संचालक आत्मा समिति एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण बालाघाट के माध्यम से 20 कृषकों के दल ने 3 दिनों तक अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षण लेकर इसके उत्पादन की तकनीक समझी। केंद्र ने प्रत्येक कृषकों को 2-2 किलोग्राम बीज अनुसंधान केंद्र से उपहार देकर कृषकों का हौसला बढ़ाया। बीज को इस वर्ष कृषकों ने अपने खेतों में भी लगाया है। मध्यप्रदेश के कृषकों को मखाना अनुसंधान केंद्र के डॉ. मनोज कुमार, उद्यान विभाग की सहायक निदेशक डॉ. आभा कुमारी, अनुसंधान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. आईएस, सिंह लनामिवि की डॉ. अपराजिता कुमारी, डॉ. मो. मोनोब्ब्ल्लाह एवं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मखाना उत्पादक कृषक धीरेंद्र कुमार ने मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण आदि की आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षित किया।

कार्ड प्रशिक्षणार्थियों ने कृषि विज्ञान केंद्र में देखी तकनीक

भोपाल। मैनेज हैदराबाद के सहयोग एवं परियोजना संचालक आत्मा भोपाल के मार्गदर्शन में कृषि सेवा केन्द्र संचालन के लिए एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र (नकतरा) रायसेन में कार्ड संस्था द्वारा आयोजित किया गया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. स्वप्निल दुबे के प्रयासों से केंद्र में विभिन्न रबी फसलों के प्रदर्शन, ग्रीनहाउस की तकनीकों को समझने का मौका प्रशिक्षणार्थियों को मिला। कार्ड के कृषि विशेषज्ञ डॉ. लालचंद यादव के साथ पहुंचे छात्रों ने कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ आरएस राघव एवं सुनील कैथवास से बीज उत्पादन तकनीक, बीजों की प्रजाति, उर्वरक कीटनाशक दवाओं के उपयोग, मिट्टी की सेहत सुधारने, नरवाई प्रबंधन जैसी कई तकनीकों को विस्तारपूर्वक समझा एवं कृषि उत्पादन में आ रही समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। भ्रमण के दौरान वन विभाग की अमरावत नर्सरी को भी देखा यहां विभाग के अमित विश्वकर्मा ने विभिन्न वृक्षों की उत्पादन तकनीक एवं उनके उपयोग, नर्सरी प्रबंधन, ग्रीनहाउस, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन आदि तकनीकों पर छात्रों का मार्गदर्शन किया। प्रशिक्षणार्थियों में शामिल डॉ. पुष्पा शर्मा, कृति मीणा, कमल सिंह गौर, सागर यादव, कार्तिक राजपूत ने अपने अनुभव व्यक्त किए।

केवीके डिंडोरी में गार्डन कीपर प्रशिक्षण आयोजित

डिंडोरी। जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में गार्डन कीपर का 210 घंटे का प्रशिक्षण डॉ. दिनकर प्रसाद शर्मा, संचालक विस्तार सेवायें, डॉ. एसआरके सिंह, निदेशक, अटारी जोन-9, डॉ. पीएल अम्बुलकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी के मार्गदर्शन में सम्पन्न कराया गया।

प्रशिक्षण प्रभारी अवधेश कुमार पटेल ने बताया कि डिंडोरी जिले के विभिन्न ग्रामों से 25 युवाओं और युवतियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों को उद्यानिकी से संबंधित गतिविधियां जैसे- फल, फूल, सब्जी की नर्सरी तैयार करना और उसकी देखभाल, बगीचे तैयार करना और उनकी देखभाल, नए पौधे-कटिंग, ब्रांडिंग, ग्राफ्टिंग आदि विधियों से तैयार करना, उद्यानिकी फसलों की खेती से संबंधित जानकारी के साथ-साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता आदि का भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पुस्तिका, टूल किट, और केंद्र द्वारा प्रकाशित साहित्य दिए गए। प्रशिक्षण समापन पर कृषि विज्ञान केंद्र से डॉ. गीता सिंह, वैज्ञानिक कृषि विस्तार, श्वेता मसराम, फसल उत्पादन विशेषज्ञ भी उपस्थित थे।

हर कोई चाहता है देखना: आज दशहरी आम लखनऊ की शान बन गया

गांव वालों की मानें तो कुछ साल पहले पेड़ सूख गया था

दशहरी आम का 200 साल पुराना पेड़ इसी पेड़ से तोड़ा गया थ पहला आम

लखनऊ। जागत गांव हमार

भारत में आम की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है। देश की मिट्टी में आम की हजारों प्रजातियों के फल चखने को मिलते हैं, लेकिन बात करें देसी आम की तो इस जैसी स्वाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। सभी की जुबान पर दशहरी आम का चस्का चढ़ा हुआ है। यूपी में ही दशहरी आमों का उत्पादन होता है। यहीं ये दूसरे देशों में इस प्रजाति के आम निर्यात किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दशहरी आम का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है।

दशहरी के नाम पर रख दशहरी नाम: लखनऊ के निकटवर्ती काकोरी में यह दशहरी गांव स्थित है। माना जाता है कि इसी गांव के 200 साल पुराने पेड़ से पहला दशहरी आम मिला था। गांव वालों से मिलकर इस आम का नाम गांव दशहरी के नाम पर रख दिया। आज 200 साल बाद भी ना तो दशहरी आम का स्वाद बदला है और ना ही वो पेड़, जिससे दुनिया का पहला दशहरी आम मिला था। आज दशहरी आम लखनऊ की शान बन गया है। देश-विदेश के लोग इसका स्वाद चखते हैं। हर पेड़ से कई टन फलों का उत्पादन मिलता है। लेकिन दुनिया का पहला दशहरी आम देने वाला पेड़ कुछ खास है। आज 200 साल बाद भी ये पेड़ सही सलामत अपने स्थान पर खड़ा है।

नवाब मोहम्मद अंसार अली ने लगवाया था पेड़

आम का सीजन आते ही इस बुजुर्ग पेड़ पर फिर से फलों के गुच्छे लग जाते हैं, लेकिन रुतबा ही कुछ ऐसा कि इस पेड़ का एक भी फल बेचा नहीं जाता। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो दशहरी गांव में इस पेड़ को नवाब मोहम्मद अंसार अली ने लगवाया था और आज उनके परिवार के लोग ही इस पेड़ पर मालिकाना हक रखते हैं। इसी परिवार को पेड़ के सारे आम भेज दिए जाते हैं।

एक बार सूख चुका था पूरा पेड़

दशहरी गांव के लोग बताते हैं कि कई साल पहले इस पेड़ की टहनी को गांव वालों से छिपाकर मलीहाबाद ले जाया गया और तब ही से दशहरी आम मलीहाबादी आम के नाम से फेमस हो गया। गांव वालों की श्रद्धा देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो इसे एक चमत्कारी पेड़ मानते हैं। गांव वालों की मानें तो कुछ साल पहले ये पेड़ पूरी तरह से सूख चुका था। सारी पत्तियां झड़ गई थीं, लेकिन आज के टाइम पर सीजन आते ही 200 साल पुराना ये पेड़ आम से लद जाता है।

फिल्म जगत के कई सेलिब्रिटी आ चुके देखने

जानकारी के लिए बता दें कि दशहरी गांव आज मलीहाबाद इलाके में आता है। मलीहाबाद के लोग बताते हैं कि कभी मिर्जा गालिब भी कोलकाता से दिल्ली की यात्रा करते थे तो मलीहाबादी आम का स्वाद जरूर चखते थे। आज भी कई सेलेब्रिटी दशहरी आम के शौकीन हैं। दशहरी गांव के लोग बताते हैं कि भारतीय फिल्म जगत के कई अभिनेता इस पेड़ का दीदार करने गांव आ चुके हैं। दूसरे गांव से भी लोग इस पेड़ को देखने आते हैं। इसकी छांव में बैठते हैं और ठंडी हवा का लुफ्त उठाने के बाद इस पेड़ की यादों को तस्वीरों में कैद करके ले जाते हैं।

बनारसी लंगड़ा को मिला जीआई टैग

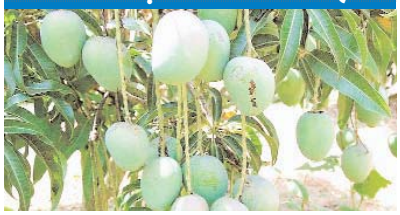

बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग मिल गया है, बनारस के ही रामनगर भांटा (बैंगन) व आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने से अब इनकी इंटरनेशनल पहचान बनेगी। पूरी दुनिया अब लंगड़ा आम का स्वाद चखेगी। अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में अब लंगड़ा आम एक्सपोर्ट किया जाएगा। जाहिर है कि इससे इन उत्पादों के कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा होगा। नाबार्ड और उत्तर प्रदेश की सरकार की मदद से वाराणसी के इन चारों उत्पादों को जीआई टैग मिल सका है। इससे पहले भी बनारस ब्रोकेड और साड़ी, मेटल रेपोसी क्राफ्ट, गुलाबी मीनाकारी, बनारस जरदोजी, बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट, बनारस वुड कार्विंग समेत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के कुल 22 उत्पादों को अब तक जीआई टैग मिल चुका है। पूरे प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जीआई टैग वाले उत्पादों की तादाद बढ़कर अब 45 हो गई है।

क्या होता है जीआई टैग

जीआई टैग ऐसे उत्पादों को पहचान देने की प्रक्रिया है जिस उत्पाद की वजह से संबंधित रीजन/क्षेत्र की खास पहचान होती है। यह टैग प्राकृतिक, कृषि और निर्मित उत्पादों की विशिष्टता और गुणवत्ता का आश्वासन देता है। साथ ही उक्त उत्पाद को कानूनी संरक्षण भी मिलता है। जीआई टैग मिलने से विदेशों में उस उत्पाद का महत्व और कीमत बढ़ जाती है।

मिश्री की तरह होती है जर्दालु आम की मिठास

देश के सभी राज्यपाल और एलजी को दिया जाएगा बिहार का प्रसिद्ध जर्दालु आम

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने फैसला किया है कि वह इस बार देश के सभी राज्यपाल और उप-राज्यपालों को जर्दालु आम भेजेगा। यानी राज्यपाल के साथ-साथ राजभवन के अधिकारी भी बिहार के फेमस जर्दालु आम का स्वाद चखेंगे। वहीं, जानकारों का कहना है कि कृषि विश्वविद्यालय ने जर्दालु आम की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने के लिए यह फैसला लिया है। तो आज जानते हैं, आखिर जर्दालु आम में कौन सी खासियत है जिसकी वजह से इसे देश के सभी राजभवनों को गिफ्ट में देने का निर्णय लिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे तो उत्तरी बिहार में कई तरह के आम की किस्मों की खेती की जाती है, लेकिन इनमें जर्दालु आम सबसे ज्यादा फेमस है। यह अपने उमदा स्वाद के लिए जाना जाता है। इसकी मिठांस मिश्री की तरह होती है। इसमें रेशे न के बराब होते हैं।

यही वजह है कि जर्दालु आम मुंह में डालते ही मक्खन की तरह पिघल जाता है। इसे लोग जूस निकालने के लिए खूब उपयोग करते हैं।

भागलपुर की पहचान है जर्दालु आम

भागलपुर की पहचान ही जर्दालु आम से है। यहां पर सबसे अधिक जर्दालु के ही बाग हैं। यह आम की एक अगेली किस्म है। ऐसे तो आम में मंजर बसंत के बाद आने शुरू होते हैं, लेकिन इसमें जनवरी महीने से ही मंजर आने लगते हैं। 20 फरवरी के बाद टिकोले आम का रूप धारण कर लेते हैं, जो जून महीने से पकने लगते हैं। हालांकि, इससे पहले ही यह खाने के लिए मार्केट में आ जाता है। यह आम आकार में काफी बड़ा होता है। इसके एक आम का वजन 200 ग्राम से अधिक होता है। साथ ही इसका छिलका थोड़ा मोटा होता है। इसलिए लोग इसे अचार लगाने में भी बहुत उपयोग करते हैं।

एक हेक्टेयर के बगीचे से 25 टन आम की पैदावार मिलती है

जर्दालु आम को पहचान करने का सबसे आसान तरीका उसका रंग है। पक जाने के बाद जर्दालु आम का कलर हलका पीला और नारंगी हो जाता है। ऐसे में लोग इसी आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें लगभग 67 प्रतिशत गूदा होता है। रेशा तो बिल्कुल नहीं होता है। इसके एक पेड़ से एक सीजन में आप 2000 फल तोड़ सकते हैं। एक हेक्टेयर के बगीचे से 25 टन आम की पैदावार मिलती है। बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर इससे पहले भी कई नेताओं और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को जर्दालु आम भेज चुका है। पिछले साल इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को जर्दालु आम गिफ्ट किया था। साथ ही यह विदेशों में भी नामचीन लोगों को गिफ्ट करता रहता है।

एक ऐसा पेड़, जिस पर लगते हैं 121 प्रजातियों के आम

सहारनपुर, सहारनपुर के कंपनी गार्डन में आम के एक 15 साल पुराने पेड़ पर 121 किस्म के फल की पैदावार होती है। करीब पांच साल पहले कंपनी बाग में यह अनोखा प्रयोग किया गया था, जिसका मकसद आम की नई-नई किस्म पर शोध करना था। साथ ही आम के शौकीनों को एक ही जगह पर कई आम की कई किस्मों का स्वाद देना भी था जो कि आज सफल हो गया है।

करीब पांच साल पहले सहारनपुर के कंपनी बाग में आम के पेड़ पर अनोखा प्रयोग किया गया था। औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र के तत्कालीन संयुक्त निदेशक राजेश प्रसाद ने आम के एक ही पेड़ पर 121 किस्म के आम की कलम(ब्रांच) लगाई थी। यही वजह है कि आम के एक ही पेड़ पर 121 तरह के आम लगने शुरू हुए हैं। शोध के लिए जिस पेड़ को चुना गया था, उसकी उम्र उस वक्त करीब 10 साल की थी।

कैसे लगाई थीं आम की कलमें

आम के देसी पेड़ की शाखाओं पर अलग-अलग किस्मों के आमों की कलमें लगाई गई थीं। पेड़ की देखरेख के लिए अलग से नर्सरी इंचार्ज की नियुक्ति की गई थी। अब इस पेड़ पर अलग-अलग तरह की प्रजाति के दशहरी, लंगड़ा, चौंसा, रामकेला, आम्रपाली, सहारनपुर अरुण, सहारनपुर वरुण, सहारनपुर सौरभ, सहारनपुर गौरव, सहारनपुर राजीव जैसे आम लगते हैं। वहीं लखनऊ सफेदा, टॉमी ऐट किंग्स, पूसा सूर्या, सैंसेशन, रटौल, कलमी मालदह आम, बांबे, स्मिथ, मैंगीफेरा जालोनिया, गोला बुलंदशहर, लरन्कू, एलआर स्पेशल, आलमपुर बेनिशा, असौजिया देवबंद समेत 121 किस्म के आम इस पेड़ पर लग रहे हैं।

ई प्रजातियों पर भी शोध जारी

अब नई प्रजातियों पर भी शोध कार्य चल रहे हैं, जिससे बेहतर किस्म के आम की पैदावार की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जो लोग आम के शौकीन हैं, वो अपने किचन गार्डन या अपने निजी फार्म हाउस पर भी इसी तरह का प्रयोग करके आम की कई किस्मों का आनंद ले सकते हैं।

बिना ड्राइवर के खेत की जुताई कर पाएंगे किसान, होगी बचत

आ गया रिमोट कंट्रोल से चलने वाला ड्राइवरलैस ऑटोमैटिक ट्रैक्टर

भोपाल। जागत गांव हमार

खेती-किसानी के कामों को आसान बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। प्रतिदिन किसानों की मद के लिए तमाम मशीनें, टूल्स और वाहन इजाद किए जा रहे हैं, जो लागत प्रभावी होने के साथ-साथ किसानों की आय को दोगुना करने में मददगार हैं। इसी दिशा में काकतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, वारंगल ने किसानों को लिए एक ड्राइवरलैस ऑटोमैटिक ट्रैक्टर इजाद किया है, जिसका चौथा ट्राइल भी सफलतापूर्वक हो चुका है।

स्वचलित ट्रैक्टर की खूबियां- केटीआईएस, वारंगल के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉ. पी निरंजन ने बताया कि ड्राइवरलैस स्वचलित ट्रैक्टर के लिए 41 लाख रुपये की परियोजना राशि दी गई थी। इस ट्रेक्टर के फीचर्स को लेकर इस प्रोजेक्ट के हैड अन्वेषक एमडी शरफुद्दीन वसीम ने बताया कि ये स्वचालित ट्रैक्टर किसानों को सुविधाजनक ढंग से खेतों की जुताई करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि ये लागत प्रभावी ट्रेक्टर खेती में किसानों का खर्च और समय बचाएगा। साथ ही किसानों की आय को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। विशेषज्ञों ने बताया कि इस ट्रैक्टर को इजाद करने का प्रमुख लक्ष्य खेती में मानव श्रम को कम करना है। इस ट्रैक्टर को ठीक उसी तरह डिजाइन किया गया है। किसान एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस से इस ट्रैक्टर का संचालन कर सकते हैं।

एंड्रॉयड एप्लीकेशन से चलेगा ट्रैक्टर

सीएसई के प्रोफेसर निरंजन रेड्डी ने बताया कि स्वचालित ऑटोमैटिक ट्रेक्टर को कंप्यूटर गेम की तरह ही एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन की मदद से संचालित कर सकते हैं। इसमें लाइफ फील्ड से डेटा इकट्ठा करने के लिए विशेषज्ञों ने सेंसर भी लगाए हैं, जो स्थान विशेष पर काम करने के लिए तापमान और मिट्टी की नमी का भी पता लगाने में मदद करेंगे। इससे मिट्टी की कमियों का भी पता लगाकर डेटा कलेक्शन में भी आसानी रहेगी।

किसानों को सचेत करने मोबाइल पर आएगा मैसेज

छुट्टा पशुओं से मिलेगा छुटकारा, खेत में जानवर के आते ही बजेगा हूटर

भोपाल। जागत गांव हमार

इस समय किसानों के लिए छुट्टा पशु समस्या का कारण बने हुए हैं। खासकर उप्र के किसान इस समस्या से खासे प्रभावित हैं। किसानों की इस परेशानी को समझते हुए एक नई तकनीक इजाद की गई है। किसानों को छुट्टा पशुओं से राहत दिलाने के लिए गोरखपुर स्थित बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी के इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन विभाग ने ऐसा हूटर बनाया है जो खेत के पास जानवर के आते ही बजने लगेगा। साथ ही किसान के मोबाइल पर इसका मैसेज भी आएगा, जिससे उसे आगाह होने में मदद मिलेगी। इस हूटर को बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र हर्ष कुमार मिश्रा, शिवम कुमार चौरसिया, आदित्य कसौधन और अनिल कुमार चौधरी ने तैयार किया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित इस अनोखे यंत्र को करीब एक माह के भीतर इन छात्रों ने तैयार किया है।

इस हूटर का नाम आईओटी क्रॉप रक्षक रखा गया है। अभी इस यंत्र का प्रोटोटाइप इन छात्रों ने प्रस्तुत किया है। इन छात्रों का दावा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तहत तैयार हुए इस यंत्र से खेतों में छुट्टा पशुओं से हो रहे फसलों के नुकसान को बचाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से जुड़े छात्र हर्ष कुमार मिश्रा ने बताया कि वे भी खेती वाले बैकग्राउंड से आते हैं और छुट्टा पशुओं से परेशान रहे हैं। इस वजह से उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाने का सोचा जिससे किसानों को राहत मिल सके।

डिवाइस की ऐसे हुई कोडिंग

प्रोजेक्ट से जुड़े छात्र शिव कुमार चौरसिया ने बताया कि इस यंत्र को दो महीने तक एक गांव में रखकर बाकायदा टेस्ट किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। टेस्टिंग के बाद ही डिवाइस को लांच किया गया है। इस डिवाइस में ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया है, जिससे यह किसानों तक सूचना या अलर्ट को पहुंचा सकता है। इस यंत्र में सॉइल मॉइस्चर सेंसर भी लगाया गया है, जिससे खेत की नमी को मापा जा सकता है।

मोबाइल पर भेजेगा एसएमएस यदि उस समय कोई भी जानवर आस-पास मौजूद रहेगा तो यह डिवाइस अगले ही पल उस खेत के मालिक किसान के मोबाइल पर एक एसएमएस अलर्ट भेजेगा। इससे किसान को यह सूचना मिल जाएगी।

यंत्र ऐसे करेगा काम

हर्ष कुमार मिश्रा ने बताया कि आईओटी क्रॉप रक्षक में वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ है जो इंटरनेट से 24 घंटे कनेक्ट रहेगा। इस यंत्र में एक सिम लगाया गया है जो हॉटस्पॉट क्रिएट करेगी और इस प्रोटोटाइप में लगे सभी डिवाइस को आपस में जोड़े रखेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट में ऊपर की तरफ एक सोलर पैनल लगाया गया है जो इस यंत्र को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराएगी। इस यंत्र में एक वाइड रेंज का कैमरा लगाया गया है, जिसमें नाइट विजन भी है। लिहाजा जब कोई भी पशु इस कैमरे की रेंज में आएगा तो इस यंत्र में लगा डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा जिससे हूटर अपने आप बजना शुरू हो जाएगा।

बनाने में पचास हजार का खर्च इस प्रोजेक्ट से जुड़े छात्र आदित्य कसौधन ने बताया कि इस यंत्र के प्रोटोटाइप को बनाने में लगभग 50,000 रुपए का खर्च आया है। इस यंत्र में लगे सारे उपकरण बहुत ही अत्याधुनिक और हाईटेक हैं। इसलिए खर्चा थोड़ा ज्यादा है लेकिन इसके परिणाम बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। ऐसा करने से किसान बहुत हद तक अपने खेतों को छुट्टा पशुओं से बचा सकेंगे। इस कॉलेज के निदेशक ने बच्चों की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है।

लेजर लैंड लेवलर मशीन कैसे करती है काम, यहां समझे पूरा तरीका

भोपाल। जागत गांव हमार

अच्छी फसल उत्पादन के लिए खेत की भूमि का समतल होना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। खेत की भूमि का उबर-खाबड़ होने से किसानों को फसल की बुआई करने, फसलों को उर्वरक देने एवं सिंचाई करने मे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज कुछ ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं जिसके इस्तेमाल से खेत को आसानी से समतल बनाया जा सकता हैं। ये मशीन न सिर्फ किसानों का समय बचाती हैं, बल्कि पैसे की भी बचत करती हैं।

लेजर लैंड लेवलर खेत की भूमि को समतल करने की मशीन हैं। यह यंत्र अत्याधुनिक तकनीक से बना हैं। यह परंपरागत विधियों से एकदम हटकर खेत की भूमि को समतल करता हैं।

इस मशीन से खेत को समतल करने के लिए मशीन को ट्रैक्टर मे जोड़कर चलाया जाता है ट्रेक्टर की क्षमता 30-35 एचपी होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। लेजर लैंड लेवलर में लेजर ट्रॉन्समीटर, विधुत नियंत्रण पैनल, डबल सोलेन्याइड हाईड्रोलिक नियंत्रण वाल्व, लेजर रिसीवर, दो पहिये और समतल करने वाले बकेट लगे होते हैं। इन सभी पार्ट्स की अलग-अलग कार्य एवं विशेषता हैं।

लेजर लैंड लेवलर मशीन से लाभ

- खेत की भूमि समतल हो जाने से पानी का अधिकतम उपयोग होता है, जिससे लगभग 30 से 40 प्रतिशत पानी की बचत होती है।
- खेत समतल हो जाने से खेत मे पानी लगने की समस्या नहीं होती हैं और जरूरत पड़ने पर खेत से पानी को निकालने मे भी आसानी होती हैं।
- खेत की भूमि का समतलीकारण होने से फसल की बोवनी करते समय बीज उबर- खाबर, ऊंची नीची जगह में नहीं जाती है जिसके कारण बीज का जमाव अच्छे से होता हैं।
- परंपरागत रूप से समतल करने के तुलना मे इस मशीन से समतल करने पर कम समय और कम मेहनत लगता हैं।
- खेत समतल होने से फसलों मे पानी का एक समान वितरण होता है।

भोपाल स्थित केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने विकसित किया है ये उपकरण

सोलर असिस्टेड ई-प्राइम मूवर मशीन: एक मशीन कई काम

भोपाल। जागत गांव हमार

खेतों की निराई-गुड़ाई और कीटनाशकों का छिड़काव करने में किसानों को बहुत अधिक समय लगता है। इन कामों में श्रम यानी मेहनत भी अधिक लगती है। किसानों के लिए इन कामों के लिए मजदूर ढूंढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सोलर असिस्टेड ई-प्राइम मूवर मशीन छोटे से लेकर बड़े किसानों तक के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे उनके समय की तो बचत होगी ही, साथ ही मजदूरों की समस्या भी दूर होगी। मशीन कुछ ही घंटे में निराई-गुड़ाई से लेकर कीटनाशक छिड़कने तक का काम कुशलता से कर लेती है। कृषि के आधुनिकीकरण में यह कृषि यंत्र बहुत महत्वपूर्ण है।

कई आधुनिक उपकरणों से लैस ई-प्राइम मूवर मशीन

सोलर असिस्टेड ई-प्राइम मूवर को केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल ने विकसित किया है। इस मशीन की खासियत है कि यह सौर उर्जा के साथ ही बैटरी से भी चल सकती है। इसमें डैशबोर्ड बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम, इमरजेंसी स्टॉप स्विच, डिजिटल स्पीड इंडिकेटर, लोड करंट और वोल्टेज मॉनिटरिंग सिस्टम, सेफ्टी स्विच और अन्य सभी सुरक्षा उपकरण लगे हुए हैं।

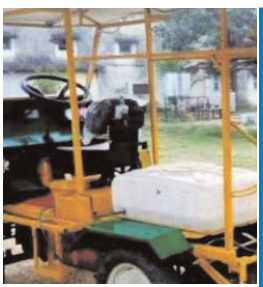

कम समय में कुशलता से काम ई-प्राइम मूवर मशीन की मदद से सवा एकड़ क्षेत्र में एक घंटे मे ही दवा का छिड़काव किया जा सकता है। जबकि सवा एकड़ ज़मीन की जुताई और निराई-गुड़ाई का काम यह मशीन 5 घंटे में ही कर देती है।

घर के काम में इस्तेमाल

ई-प्राइम मूवर मशीन का इस्तेमाल घर में लाइट जलाने के लिए भी किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से चार्ज हुई इसकी बैटरी से घर की लाइट जला सकते हैं। यह उपकरण 2 क्विंटल तक का भार उठा सकता है। यानी खेत से 2 क्विंटल अनाज आसानी से घर ले जा सकते हैं। अगर इसे बैटरी से चला रहे हैं तो फुल चार्ज करने पर बैटरी 3 घंटे चलती है।

सोलर असिस्टेड ई-प्राइम मूवर मशीन की खासियत

- यह बिना ईंधन के चलता है। बैटरी या सोलर एनर्जी इसके लिए जरूरी है।
- बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद 3 घंटे तक चलती है।
- इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती।
- यह पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी इसे चला सकता है।
- 2 क्विंटल तक अनाज का बोझ ढो सकता है।
- सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली बैटरी से आप घर की बिजली भी चला सकते हैं।

किसानों को होगी अधिक बचत यह मशीन समय और श्रम की बचत तो करता ही है, साथ ही ईंधन की भी बचत करता है जिससे किसानों की खेती की लागत कम और मुनाफा अधिक होता है।
कितनी है कीमत सौर पैनल के साथ मशीन की कीमत करीबन 3.10 लाख रुपए और बिना सौर पैनल के 1.80 लाख रुपए के आसपास है। इस ऑपरेटिंग लागत 500 रुपए प्रति घंटा है।

क्रेंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मेहनत रंग लाई, 416.96 करोड़ से बनेगा 63 किमी लंबा गोरस श्यामपुर हाईवे

वन्यप्राणियों के लिए हाइवे के नीचे बनेगा रास्ता, ऊपर से निकलेंगे वाहन

तीन चरणों में बनने जा रहे श्योपुर-मुरैना-नेशनल हाईवे-552 के दूसरे चरण के सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। दूसरे चरण में गोरस से श्यामपुर तक 63 किमी लंबे हाईवे का निर्माण होगा, इसके लिए 416.96 करोड़ रुपए की मंजूरी शासन से मिल गई है। इसमें से 259 करोड़ रुपए सड़क बनाने पर खर्च किए जाएंगे। बाकी राशि बिजली पोल शिफ्टिंग, नाली, फोरेस्ट लैंड का डायवर्सन आदि पर खर्च होगी। टू लेन बनने वाला यह हाइवे 10 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा जिसमें डेढ़-डेढ़ मीटर के शोल्डर भी रहेंगे। यह स्वीकृति केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई है।

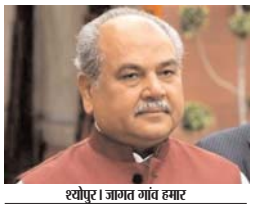

श्योपुर। जागत गांव हमार

राजस्थान के टोंक से यूपी के चिरगांव तक बनने वाले नेशनल हाईवे 552 का राजस्थान सीमा में काम कंपलीट हो चुका है। जबकि श्योपुर और मुरैना जिले की सीमा में यह नेशनल हाईवे तीन चरणों में बनाया जा रहा है। पाली से गोरस तिराहे तक पहले चरण के निर्माण कार्य को स्वीकृति मिल गई है। वहीं अब गोरस से श्यामपुर तक दूसरे चरण के निर्माण कार्य को शासन के द्वारा स्वीकृति दी गई है। गोरस से श्यामपुर के बीच जंगल क्षेत्र भी है और यह जंगल का रास्ता कूनो सेंचुरी को राजस्थान की रणथंभोर सेंचुरी से भी जोड़ता है तथा इसी रास्ते से रणथंभोर सेंचुरी के वन्य जीव कूनो सेंचुरी तक पहुंच जाते है।

हाईवे के बनने से इन जंगली जानवरों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए हाईवे के नीचे जंगली जानवरों के लिए रास्ता दिया जाएगा। यानी नीचे जानवरों के निकलने के लिए रास्ता होगा और ऊपर सड़क, जिससे वाहन निकलेंगे। गोरस-श्यामपुर हाइवे 10 मीटर चौड़ा बनेगा। जिसमें 7 मीटर में डामर और तीन मीटर में डेढ-डेढ मीटर के शोल्डर दोनों तरफ रहेंगे।

इस हाइवे पर कुल 4 बड़े पुल बनाए जाएंगे, जिन पर लगभग 24 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसके अलावा 13 करोड़ लागत से दो छोटे पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। जबकि श्यामपुर से सबलगढ़ तक हाईवे का निर्माण तीसरे चरण के तहत होगा। करीब 55 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भिजवा दिया है, जिसकी अभी स्वीकृति मिलने का इंतजार बना हुआ है।

483 करोड़ में बनेगा पाली से गोरस तक का हाईवे

पहले चरण के तहत राजस्थान बॉर्डर के पाली पुल से गोरस तक हाइवे का निर्माण होगा। जो 48.40 किमी लंबा बनेगा। इसके लिए 483.21 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति शासन से मिल चुकी है। एनएचएआई के सब इंजीनियर विजय अवस्थी ने बताया कि पहले चरण की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी धरातल पर शुरू हो जाएगा।

पाली पुल से गोरस तक बनेंगे तीन बायपास

पाली पुल राजस्थान बॉर्डर से गोरस तक के हिस्से में तीन बायपास सड़क बनाई जाएंगी। इसमें पहला बायपास दांतरदा कलां पर 3.05 किमी लंबा बनेगा। दूसरा बायपास सोंईकलां पर 3.18 किमी लंबा होगा। तीसरा और इस हिस्से का सबसे बड़ा बायपास रोड श्योपुर बायपास होगा, जो 7.95 किमी का होगा। इसमें नहर पर नवीन पुल का निर्माण भी शामिल है।

सीधा खेत से माल उठा रहे व्यापारी, किसान भी खुश

दुबइ-सऊदी-अरब और ओमान में हरदा की मिर्च का जलवा

हरदा। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के हरदा जिले की हरी मिर्च का तीखापन अरब देशों को भा रहा है। यही कारण है बीते 5 महीने में करीब 12 हजार मिट्रिक टन से ज्यादा हरी मिर्च यहां से सऊदी अरब और अन्य शहरों को एक्सपोर्ट हुई है। स्वाद में तीखी और ज्यादा समय तक ताजी बनी रहने की विशेषता के कारण जिले की हरी मिर्च की मांग विदेशी बाजार मे बढ़ गई है। जिले से सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, ओमान जैसे देश के लोग हरदा की मिर्च और उससे बने उत्पादों का स्वाद चख रहे हैं।

गौरतलब है कि देश और प्रदेश में गेंहू उत्पादन में मिनी पंजाब के नाम से पहचाना जाना वाला हरदा अब हरी मिर्च के उत्पादन में आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब के आलावा दुबई, ओमान, कतर जैसे देशो में हरदा की हरी मिर्च एक्सपोर्ट की जा रही है। मुंबई से व्यापारी सीधे हरदा जिले के किसानों से संपर्क कर रहे हैं। वे खेतों से ही बाजार भाव से हरी मिर्च उठा रहे हैं। इससे किसानों का खर्च की बच हो रही है। साथ ही उनको अच्छे दाम भी मिल रहे हैं।

जिले से हरी मिर्च विदेशो में निर्यात की जा रही- तिवारी

हरदा जिले में उद्यानिकी विभाग के एसडीओ योगेश तिवारी ने बताया कि जिले में हरी मिर्च का रकबा बढ़ा है। जिले से हरी मिर्च विदेशो में निर्यात की जा रही है। हरी मिर्च को विदेशो में प्रोसेसिंग कर चिली सॉस, ग्रीन पावडर, चिली ऑयल बनाए जा रहे हैं। इससे इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।

कृषि मंत्री ने वार्ड चौपाल में हितलाभ वितरित किए

भोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा के वार्ड 5,6 और 7 की वार्ड चौपाल में शामिल होकर जनता की समस्याएं सुनी। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्व-रोजगार योजना के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। मंत्री ने कहा कि जनता को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सभी के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने वार्ड चौपाल में अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पात्र हितग्राहियों को हर हाल में लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें, किसी प्रकार की कोताही न बरते। मंत्री ने ग्राम पंचायत धनगांव, ग्राम बुंदड़ा में 15 लाख रुपए की लागत के स्टॉप डेम निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। जिला पंचायत हरदा उपाध्यक्ष दर्शन सिंह, अमर सिंह मीणा और अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)